रामेश्वर दयाल

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

(न्यायमूर्ति बी.पी. सिन्हा, सी.जे., एस.के. दास, के.सी. दास गुप्ता, एन. राजगोपाल अयंगर और जे. आर. मुधोलकर)

जिला न्यायाधीश-नियुक्ति के लिए पात्रता-संविधान के तहत नियुक्ति-योग्यताएं-अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिस की अवधि, यदि इसमें लाहौर उच्च न्यायालय-उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947, खंड 6-बार काउंसिल अधिनियम, 1926 (1926 का 38) में प्रेक्टिस की अवधि शामिल है, भारत के संविधान की धारा 8, अनुच्छेद 233(2)

जिला न्यायाधीशों के रूप में उत्तरदाता-2 से 6 की नियुक्ति की वैधता को अपीलकर्ता द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका में चुनौती दी गई थी, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 233(2) का उल्लंघन करके की गई थी, जो यह बताता है कि “एक व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह कम से कम सात साल तक एडवोकेट या प्लीडर रहा हो। ” उत्तरदाता को

1933 और 1940 के बीच विभिन्न तिथियों पर लाहौर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था, और जबकि उत्तरदाता 2, 4 और 5 का नाम पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की सूची में था और वे उस समय अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिस कर रहे थे। उन्हें 1950 और 1952 में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जब उत्तरदाता 3 और 6 को 1957 और 1958 में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तब तथ्यात्मक रूप से उनके नाम सूची में नहीं थे। उत्तरदाता 6 का नाम उनकी नियुक्ति के बाद दर्ज किया गया था।

28 सितंबर,1948 की एक अधिसूचना के तहत, बार काउंसिल अधिनियम 1926 की उपधारा 3 से 16, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय के संबंध में लागू हुई, जिसके आधार पर एक बार काउंसिल का गठन किया गया और अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार की जानी थी और अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया। अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार उन्हें बार काउंसिल को देय 10 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। अपीलकर्ता का तर्क यह था कि देश के विभाजन के बाद, जिसके कारण पूर्वी पंजाब प्रांत के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त, 1947 को उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश 1947 के तहत की गई थी, चूंकि उत्तरदाता के पास उस तारीख के बाद भारत की किसी

अदालत में प्रैक्टिस के अधिकार के संदर्भ में अधिवक्ता के रूप में सात साल का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 233(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। जब उन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और इसलिए, उनकी नियुक्तियाँ संवैधानिक रूप से अमान्य थीं। प्रश्न यह था कि क्या अनुच्छेद 233(2) में निर्दिष्ट सात वर्ष की अवधि को भारत के क्षेत्र में एक अदालत में प्रैक्टिस के उसके अधिकार के संदर्भ में एडवोकेट या प्लीडर की स्थिति के रूप में गिना जाना चाहिए जैसा कि अनुच्छेद-I में परिभाषित किया गया है। संविधान, या क्या किसी अदालत में प्रैक्टिस का कोई अधिकार जो 1947 में देश के विभाजन से पहले भारत में था लेकिन जो विभाजन के बाद से भारत में नहीं था, को भी सात साल की अवधि की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जा सकता है।

माना गया कि उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश के 1947 के खंड (6) के तहत, बार काउंसिल अधिनियम, 1926 की धारा 8(3) के साथ पठित, पंजाब उच्च न्यायालय का एक अधिवक्ता बार में अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय में अपने प्रेक्टिस की अवधि की गणना करने का हकदार था। तदनुसार, चूंकि उत्तरदाता 2, 4 और 5 जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने पर भी पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने रहे और नियुक्ति के समय उनका कार्यकाल सात वर्ष से

अधिक था, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 233(2) की आवश्यकताओं को पूरा किया।

आगे माना गया कि उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947 के खंड (6) और बार काउंसिल अधिनियम, 1926 की धारा 8(2)(ए) का प्रभाव 15 अगस्त, 1947 से 28 सितंबर 1948 तक था, जिन अधिवक्ताओं को लाहौर उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित किया गया था, उन्हें पंजाब उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के हकदार अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता दी गई थी, और 28 सितंबर, 1948 के बाद, वे स्वचालित रूप से पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की सूची में आ गए, लेकिन बार काउंसिल को 10 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। परिणामस्वरूप, उत्तरदाता 3 और 6 जिन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी समय या चरण में अधिवक्ता बनना बंद नहीं किया, वे तब तक पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने रहे जब तक कि उन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया और संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत नियुक्ति किये जाने के संबंध में सात साल से अधिक की स्थिति होने की शर्त की पूर्ति करते थे।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 438/1960

1959 की सिविल रिट संख्या 1050 में पंजाब उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के 21 सितंबर, 1959 के फैसले से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

ए.एस.आर. चारी, एम.एस.के. शास्त्री और के.एल. मेहता, अपीलकर्ता के लिए

एस.एम.सीकरी, पंजाब के महाधिवक्ता एन.एस.बिन्द्रा, के.एल.अरोडा और डी.गुप्ता उत्तरदाता सं.1 के लिए

गुरबकन सिंह, तीर्थ सिंह मुंजराल और आर. एच. ढेबर, उत्तरदाता क्रमांक 2, 3 और 5 के लिए।

ए. वी. विश्वनाथका शास्त्री, आर. गणपति अय्यर और डी. गुप्ता, उत्तरदाता संख्या 4 और 6 के लिए।

एच. एन. सान्याल, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल, जेएल और डी. गुप्ता हस्तक्षेपकर्ता (भारत संघ) के लिए|

एम.के.नांबियार, एम.एस.के.शास्त्री और के.एल.मेहता हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए (ओमदत्त शर्मा और बी.डी.पाठक)

05 दिसंबर 1960 को न्यायालय का निर्णय सुनाया गया ।

न्यायमूर्ति एस.के. दास- यह पंजाब उच्च न्यायालय के 21 सितंबर, 1959 के एक आदेश की विशेष अनुमति द्वारा की गई अपील है, जिसके द्वारा उसने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कुछ राहतों के लिए वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा की गई याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया था। पांच व्यक्ति, जिनमें से दो अब पंजाब उच्च न्यायालय के

अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं, तीसरा उसी न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में, चौथा जिला और सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के रूप में, और पांचवां रजिस्ट्रार, पंजाब उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के रूप में काम कर रहा है। उन विवरणों को छोड़ दें जो भौतिक नहीं हैं, अपीलकर्ता का मामला यह था और है कि उपरोक्त पांच व्यक्ति, जो अब हमारे सामने उत्तरदाता स. 2 से 6 हैं, उस समय संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया थे, जो अब हमारे सामने उत्तरदाता है, और इसलिए, उनकी नियुक्ति संवैधानिक रूप से अमान्य थी; और अपीलकर्ता ने अपनी मुख्य राहत के माध्यम से दावा किया कि Quo warranto की प्रकृति में एक रिट जारी की जानी चाहिए "उन्हें उनके कार्यालय से बाहर निकालना और उन्हें उनके द्वारा धारण किए गए पदों की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का प्रयोग करने और दावा करने से रोकना चाहिए।" उनके कार्यालय से जुड़े कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार या परिलब्धियाँ।" कुछ अन्य सहायक या सहायक राहतों का भी दावा किया गया था जिनके विवरण अब बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा है कि याचिका को उच्च न्यायालय ने सरसरी तौर पर खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय में फिटनेस प्रमाण पत्र के विफल होने पर अपीलकर्ता ने 19 अगस्त, 1960 को इस न्यायालय से विशेष अनुमति मांगी और प्राप्त की।

अपील का विरोध पंजाब राज्य, उत्तरदाता-1 और अन्य उत्तरदाताओं द्वारा किया गया है जिनमें से शमशेर बहादुर, हरबंस सिंह और गुरदेव सिंह पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, हंस राज खन्ना जिला और सत्र न्यायाधीश, दिल्ली और पी. आर. साहनी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार हैं। इन उत्तरदाता ने जवाब में अलग-अलग हलफनामे दायर किए हैं, और उनमें से कुछ का अलग से प्रतिनिधित्व किया गया है और सुना गया है। पंजाब राज्य के महाधिवक्ता उपस्थित हुए और उत्तरदाता 1 की ओर से अपील का विरोध किया। भारत संघ मूल रूप से याचिका में एक पक्ष-उत्तरदाता था क्योंकि अपीलकर्ता ने शुरू में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में दो उत्तरदाता की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी; हालाँकि, यह राहत विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान छोड़ दी गई थी और अपीलकर्ता द्वारा किए गए एक आवेदन पर, 18 मार्च, 1960 के एक आदेश द्वारा भारत संघ का नाम हटा दिया गया था, जिससे मामला केवल जिला न्यायाधीशों के रूप में उत्तरदाता 2 से 6 की प्रारंभिक नियुक्ति की वैधता के प्रश्न पर, विवाद तक ही सीमित रह गया था। बाद में, भारत संघ ने अपील में हस्तक्षेप करने के लिए एक आवेदन किया और इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अपील में संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या का प्रश्न उठता है, हमने आवेदन की अनुमति दी है और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल को सुना है। भले ही भारत संघ अपीलकर्ता द्वारा किए गए आवेदन का विरोध करने के लिए इसे प्रतिक्रिया की श्रेणी

से बाहर निकालने के लिए, पहले चरण में उपस्थित नहीं हुआ|

अन्य व्यक्तियों बी.डी. पाठक और ओम दत्त शर्मा ने भी पी.आर. साहनी की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए पंजाब उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 22 जनवरी, 1959 को उनके द्वारा तय की गई तीन आपराधिक अपीलों में कुछ व्यक्तियों को बरी कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के रूप में, एक मामले में दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के फैसले से, जिसमें बी. डी. पाठक और ओम दत्त शर्मा ने कहा कि मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा उन पर हमला किया गया था। उन्होंने पारित आदेशों के संबंध में तीन पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं, जो उच्च न्यायालय में लंबित हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्तमान अपील में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति दी गई है, जहां तक यह पी.आर. साहनी की नियुक्ति से संबंधित है, और हमने उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

उत्तरदाता की ओर से जो अब जिला न्यायाधीश के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, अपील की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति ली गई है। पंजाब राज्य ने तर्क दिया है कि अपील अब जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के सवाल तक सीमित है और चूंकि वे अब जिला न्यायाधीश का पद नहीं संभाल रहे हैं, इसलिए उस संबंध में Quo warranto जारी करने

की प्रार्थना की गई है। कार्यालय अब रखरखाव योग्य नहीं है. अपीलकर्ता की ओर से उत्तर में प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाता 2 से 4 उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश नहीं हैं, इसलिए यदि और जब वे जवाब देते हैं, तो उन्हें जिला न्यायाधीशों के अपने मूल पदों पर वापस जाना होगा; इसलिए, यह प्रश्न कि क्या उन्हें वैध रूप से उनके मूल पदों पर नियुक्त किया गया था, एक जीवंत मुद्दा है और अपीलकर्ता इस न्यायालय से उस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए कहने का हकदार है। विद्वान महाधिवक्ता ने जाहिर किया है कि राज्य भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए की गई नियुक्तियों की वैधता पर इस न्यायालय के निर्णय के लिए उत्सुक है और राज्य प्रश्न के निर्धारण पर कोई प्रारंभिक आपत्ति नहीं उठाना चाहता है। मुद्दे में. मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया जाना चाहिए और इस मामले की परिस्थितियों में, इस न्यायालय को विवादित नियुक्तियों की वैधता पर निर्णय लेना चाहिए।

यदि हम पहले उन परिस्थतियों को व्यापक रूपरेखा में बताएं जिनमें उत्तरदाता 2 से 6 को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इससे विवाद के बिन्दुओं को सुगम करने में सुविधा होगी।

(1) उत्तरदाता 2 (शमशेर बहादुर, जे.) को 26 जनवरी, 1933 को मिडिल

टेम्पल द्वारा इंग्लैंड में बार में बुलाया गया था। 15 मई, 1933 को उन्हें लाहौर उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया और उन्होंने उसी न्यायालय में प्रेक्टिस किया। 9 फरवरी, 1949 को उन्हें भारत के संघीय न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। 15 अगस्त, 1947 को और उसके बाद, उन्होंने 20 मार्च, 1950 को जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने तक पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिस किया। फिर उन्होंने दिसंबर 1953 से मई 1959 तक राज्य सरकार के कानूनी स्मरणकर्ता के रूप में कार्य किया, जब उन्हें पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

2 उत्तरदाता 3 (हरबंस सिंह, जे.) को भी 1960 में बार में बुलाया गया और फिर 5 मार्च, 1937 को लाहौर उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता रामेश्वर दयाल के रूप में नामांकित किया गया। उन्होंने पंजाब राज्य, फिरोजपुर में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में काम किया। 2 जुलाई, 1947 से 22 फरवरी, 1948 तक, 15 मार्च, 1948 को फिर वह थोड़े समय के लिए शिमला में प्रेक्टिस के लिए लौट आए। उन्होंने 17 अप्रैल, 1950 तक डिप्टी कस्टोडियन, इवेक्यू प्रॉपर्टी के रूप में काम किया। 18 अप्रैल, 1950 को उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 11 अगस्त, 1958 को उन्हें पंजाब उच्च

न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

(3) उत्तरदाता 4 (गुरदेव सिंह, जे.) को 25 अक्टूबर 1934 को लाहौर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था, और फिर 20 दिसंबर 1938 को उक्त न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था। 29 मई, 1948 को भारत के संघीय न्यायालय के, और 2 फरवरी, 1952 को जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने तक लगातार प्रेक्टिस में रहे। 11 जुलाई, 1960 को उन्हें पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया।

(4) उत्तरदाता 5 (हंस राज खन्ना) को 17 जुलाई, 1934 को लाहौर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था, और फिर 20 दिसंबर, 1940 को उक्त न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था। उन्होंने अपना प्रेक्टिस शुरू किया अमृतसर में एक अधिवक्ता के रूप में और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने तक उन्होंने वहीं अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। उनका नाम पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई अधिवक्ताओं की सूची में था, जब वह 1 फरवरी 1952 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किये गये।

(5) उत्तरदाता 6 (पी. आर. साहनी) को 17 नवंबर 1930 को बार में बुलाया गया था, और 10 मार्च 1931 को लाहौर उच्च न्यायालय के एक

अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था। विभाजन के बाद वह दिल्ली चले गए और कुछ समय तक कानूनी सलाहकार कस्टोडियन, निष्क्रांत संपत्ति दिल्ली के रूप में काम किया। फिर उन्होंने कुछ समय तक दिल्ली में प्रेक्टिस की; इसके बाद उन्होंने पुनर्वास मंत्रालय के तहत विशेष कर्तव्य अधिकारी और राजपुरा टाउनशिप के प्रशासक के रूप में सेवा स्वीकार की। 30 मार्च, 1949 को वह जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। 6 मई, 1949 को उनका अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

6 अप्रैल, 1957 को उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर उल्लिखित पांच उत्तरदाता में से तीन, शमशेर बहादुर, गुरुदेव सिंह और हंस राज खन्ना का नाम जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की सूची में था। दूसरे शब्दों में, जिस समय उन्हें नियुक्त किया गया था उस समय वे अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से दो, हरबंस सिंह और पी.आर.साहनी को जब जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया तो उनके नाम तथ्यात्मक रूप से सूची में नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पी. आर. साहनी का नाम 20 अक्टूबर, 1959 को, यानी जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति के

बाद, नामांकित किया गया था। हम इस स्तर पर उत्तरदाता के बीच इस अंतर पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बाद में दिखाई देगा, इस अंतर का अपीलकर्ता की ओर से हमारे सामने दिए गए तर्कों में से एक पर कुछ असर पड़ता है।

अब हम अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किए गए मुख्य तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अर्थात जिला न्यायाधीशों के रूप में उत्तरदाता 2 से 6 की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई थी। यहां संविधान के अनुच्छेद 233 को पढ़ना सुविधाजनक है:

"अनुच्छेद 233 (1) किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और उनकी पोस्टिंग और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा यदि वह सात साल से कम समय तक एडवोकेट या प्लीडर रहा हो और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति की सिफारिश की गई हो।"

अब, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क व्यापक क्षेत्र में फैल गया है; लेकिन निर्णय का मुद्दा संकीर्ण है और यह इस पर निर्भर करता

है कि क्या उत्तरदाता-2 से 6 ने संविधान के अनुच्छेद 233 के खंड (2) की आवश्यकताओं को पूरा किया था जब उन्हें उत्तरदाता 1 द्वारा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह खंड बताता है कि एक व्यक्ति नहीं पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में होने पर ही वह जिला न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा यदि (1) वह कम से कम सात साल तक एडवोकेट या प्लीडर रहा हो और (2) उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति की सिफारिश की गई हो। जहां तक दूसरी आवश्यकता का सवाल है, पंजाब राज्य का यहां कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरदाता 2 से 6 की नियुक्ति से पहले उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई थी। विवाद पहली शर्त को लेकर है. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तरदाता- 2 से 6 ने "सात साल तक एडवोकेट या प्लीडर" रहने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है और अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित तरीके से अपना तर्क रखा है। सबसे पहले, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अभिव्यक्ति "अधिवक्ता या अधिवक्ता" कानूनी आयात की अभिव्यक्ति है और संविधान को अपनाए जाने के समय इसका आम तौर पर स्वीकृत अर्थ दिया जाना चाहिए और विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उस अभिव्यक्ति का अर्थ एक एडवोकेट या प्लीडर है जो भारत में किसी न्यायालय में उपस्थित होने और दूसरे के लिए दलील देने का हकदार है, लेकिन इसमें किसी विदेशी न्यायालय का एडवोकेट या प्लीडर शामिल नहीं है; इस प्रस्तुतिकरण के लिए उन्होंने कानूनी व्यवसायी

अधिनियम 1879 (1879 का XVIII) में "कानूनी व्यवसायी" अभिव्यक्ति की परिभाषा पर भरोसा किया है; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम V) में "अधिवक्ता" का; और बार काउंसिल अधिनियम, 1926 (1926 का XXXVIII) में "अधिवक्ता" का। दूसरे, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अनुच्छेद 233 के खंड (2) में वर्तमान सही काल के उपयोग के कारण, व्याकरण के नियमों की आवश्यकता है कि नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति न केवल पहले एक एडवोकेट या प्लीडर रहा हो। लेकिन जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के समय उसे एडवोकेट या प्लीडर होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि खंड में निर्दिष्ट सात वर्ष की अवधि को संविधान के अनुच्छेद 1 में परिभाषित भारत के क्षेत्र में एक न्यायालय में प्रैक्टिस के उनके अधिकार के संदर्भ में एडवोकेट या प्लीडर की स्थिति के रूप में गिना जाना चाहिए। ; दूसरे शब्दों में, किसी न्यायालय में प्रैक्टिस का कोई भी अधिकार जो 1947 में देश के विभाजन से पहले भारत में था, लेकिन विभाजन के बाद से भारत में नहीं है, उसे सात साल की अवधि की गणना के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

हम फिलहाल इन प्रस्तुतियों पर विचार करेंगे जहां तक वे हमारे सामने मौजूद समस्या पर आधारित हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, देश के विभाजन के बाद हुए परिवर्तनों की व्याख्या करना आवश्यक है और पूर्वी पंजाब प्रांत के लिए न्यायिक उच्च न्यायालय की स्थापना से

लेकर प्रांत के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पूर्वी पंजाब (जिसे अब पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय कहा जाता है) और उन परिवर्तनों ने उन अधिवक्ताओं या एडवोकेटस की स्थिति को कैसे प्रभावित किया, जिन्हें अविभाजित पंजाब के लाहौर उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने का अधिकार था। स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, दो स्वतंत्र डोमिनियनों-भारत और पाकिस्तान को अस्तित्व में लाया और इसकी धारा 9 ने गवर्नर-जनरल को अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी संचालन में लाने के लिए आदेश देने की शक्ति दी। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए गवर्नर-जनरल ने उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947 बनाया, जिसने नियत दिन (15 अगस्त, 1947) से तत्कालीन पूर्वी पंजाब प्रांत के लिए न्यायिक उच्च न्यायालय की स्थापना की। आदेश का खंड 6 महत्वपूर्ण है और इसे पूर्ण रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए:

"6(1) उच्च न्यायालय पूर्वी पंजाब के पास एडवोकेटस, वकीलोंं और एटोर्नी को मंजूरी देने, स्वीकार करने, नामांकन करने, हटाने और निलंबित करने और अधिवक्ताओं, एडवोकेटस और एटोर्नी के संबंध में कानून के तहत नियम बनाने की समान शक्तियां होंगी। यह नियुक्ति दिन से ठीक पहले लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया।

(2) पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार को उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार विनियमित किया जाएगा, जो नियुक्ति दिन से

ठीक पहले, लाहौर में उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार के संबंध में लागू हैं:

बशर्ते कि, इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम या दिए गए निर्देश के अधीन, कोई भी व्यक्ति, जो नियुक्ति दिन से ठीक पहले, एक अधिवक्ता, एडवोकेट या प्लीडर है, हकदार है लाहौर उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए एक अधिवक्ता, एडवोकेट या प्लीडर के रूप में मान्यता दी जाएगी जो पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है।"

आदेश के खंड 14 पर ध्यान देना भी आवश्यक है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि " पूर्वी पंजाब के द्वारा किसी विधि या अन्य प्राधिकार के तहत ऐसे प्रावधान बनाने की शक्ति प्राप्त हो। नियुक्ति दिन पर या उसके बाद किए गए किसी भी प्रावधान के अधीन प्रभावी होंगे।" प्राधिकरण के पास ऐसे प्रावधान करने की शक्ति है" जिन बिंदुओं पर हमें यहां जोर देना चाहिए वे हैं (1) पंजाब राज्य को धारा 6(2) के तहत नए उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं की वरिष्ठता को उनके सुनने के अधिकार के अनुसार विनियमित किया जाना था। पूर्व उच्च न्यायालय में लागू सिद्धांत और (2) कि खंड 6 के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 से पहले लाहौर उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार

अधिवक्ता था, उसे पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी गई थी। पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम या दिए गए निर्देश या विधायिका या ऐसे प्रावधान करने की शक्ति रखने वाले अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी प्रावधान के अधीन है। बार काउंसिल अधिनियम, 1926, उपधारा 1, 2, 17, 18 और 19 को छोड़कर, पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता था। 28 सितंबर, 1948 को एक अधिसूचना द्वारा, पूर्वी पंजाब के राज्यपाल ने निर्देश दिया कि उक्त अधिनियम की उपधारा 3 से 16 के प्रावधान उस तिथि से पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होंगे। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा। **अधिनियम की धारा 8 कहती है (हम केवल वही भाग पढ़ रहे हैं जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है):-**

"धारा 8(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के अधिकार का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसका नाम इस अधिनियम के तहत बनाए गए उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की सूची में दर्ज न हो:

बशर्ते कि इस उपधारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय के किसी भी अधिवक्ता पर लागू नहीं होगी।

(2) उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार करेगा और बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित के नाम दर्ज किए जाएंगे-

(ए) वे सभी व्यक्ति, जो अधिवक्ता, एडवोकेट या प्लीडर के रूप में, उस तारीख से ठीक पहले उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के अधिकार के हकदार थे, जिस दिन यह धारा उसके संबंध में लागू होती है; और

(बी) अन्य सभी व्यक्ति जिन्हें इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में भर्ती किया गया है:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्तियों को नामांकन के संबंध में भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत प्रभार्य स्टांप शुल्क, यदि कोई हो, और बार काउंसिल को देय शुल्क का भुगतान करना होगा, जो व्यक्तियों के खंड (ए) में निर्दिष्ट पंजाब राज्य के मामले में दस रुपये होगा, और अन्य मामलों में ऐसी राशि जो निर्धारित की जा सकती है।

(3) नामावली में प्रविष्टियाँ वरिष्ठता के क्रम में की जाएंगी और ऐसी वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी, अर्थात्:

(ए) उप-धारा (2) के खंड (ए) में निर्दिष्ट ऐसे सभी व्यक्तियों को पहले उस क्रम में दर्ज किया जाएगा जिसमें वे क्रमशः उच्च न्यायालय के संबंध में, इस धारा के लागू होने की तारीख से ठीक पहले

वरिष्ठता के हकदार थे; और

(बी) इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में भर्ती किए गए किसी अन्य व्यक्ति की वरिष्ठता; उसके बाद की तारीख उसके प्रवेश की तारीख से निर्धारित की जाएगी या, यदि वह बैरिस्टर है, तो उसके प्रवेश की तारीख से या उस तारीख से जिस दिन उसे बार में बुलाया गया था, जो भी तारीख पहले हो:-

बशर्ते कि, खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए, उस व्यक्ति की वरिष्ठता जो अधिवक्ता बनने से पहले किसी अन्य उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के अधिकार का हकदार था, उस तारीख से निर्धारित की जाएगी जिस दिन वह ऐसा हकदार बन गया था।

4) उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के संबंधित पूर्व-दर्शक अधिकार वरिष्ठता द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

हमारे सामने मौजूद रिकॉर्ड से यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में पंजाब उच्च न्यायालय के लिए बार काउंसिल का गठन कब किया गया था, लेकिन बार में यह कहा गया था कि पहला चुनाव 1950 में हुआ था। लेकिन 13 जनवरी 1949 को उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(1) में निम्न प्रावधान किये गये।

अधिनियम नियम 2(1) की उपधारा 6 और 12 के तहत कुछ नियम इन

शर्तों में थे:

"नियम 2(1) रजिस्ट्रार भारतीय बार काउंसिल अधिनियम की धारा 8, उप-धारा (2) के तहत तैयार किए गए रोल में दर्ज अधिवक्ताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत करेगा: -

(ए) वे लोग जो उच्च न्यायालय की बार काउंसिल के सदस्यों के चुनाव की तारीख पर या उससे पहले कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के अधिकार के हकदार होंगे,

(बी) जो खंड (ए) में उल्लिखित लोगों के अलावा अन्य हैं या जो उच्च न्यायालय की बार काउंसिल के सदस्यों के चुनाव की तारीख पर या उससे पहले उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस करने के हकदार हो सकते हैं"।

इसलिए, हमारे पास ध्यान में रखने के लिए दो अलग-अलग अवधि हैं। पहली अवधि 15 अगस्त, 1947 से 27 सितंबर, 1948 के बीच है, जब बार काउंसिल अधिनियम, 1926 के मुख्य प्रावधान पंजाब उच्च न्यायालय के लिए लागू नहीं थे और अधिवक्ताओं के अधिकार उच्च न्यायालयों (पंजाब) द्वारा विनियमित थे) आदेश, 1947 दूसरी अवधि 28 सितंबर, 1948 से थी, जब बार काउंसिल अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को लागू किया गया था, उसके तहत नियम बनाए गए थे, एक बार काउंसिल का गठन किया गया था और अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार की गई थी और उसके अनुसार बनाए रखा गया था। उक्त अधिनियम की धारा 8 के

साथ यह दूसरी अवधि थी जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ।

यही वह पृष्ठभूमि है जिसके विरुद्ध हमें अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार करना होगा। भले ही हम उनकी सत्यता पर अंतिम निर्णय किए बिना यह मान लें कि विद्वान अधिवक्ता अपने पहले दो प्रस्तुतियों में सही है, अर्थात अनुच्छेद 233 के खंड (2) में "अधिवक्ता" शब्द का अर्थ भारत में एक न्यायालय का अधिवक्ता है और अपनी नियुक्ति के समय ऐसे अधिवक्ता बनें। उन तीन उत्तरदाता की नियुक्ति पर उन आधारों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती जो तथ्यात्मक रूप से अपनी नियुक्ति के समय पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की सूची में थे; क्योंकि माना जाता है कि वे भारत में एक न्यायालय में अधिवक्ता थे और अपनी नियुक्ति की तारीख तक ऐसे ही अधिवक्ता बने रहे। उनके संबंध में एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या वे लाहौर उच्च न्यायालय में या उसके अधीन अपनी वकालत की अवधि को सात वर्षों की अवधि में गिन सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947 के खंड 6(2) द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसे बार काउंसिल अधिनियम, 1926 की धारा 8(3) के साथ पढ़ा जाता है। यह खंड बताता है कि दर्शकों का अधिकार पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय को नियत दिन से ठीक पहले लाहौर उच्च न्यायालय में लागू सिद्धांत के अनुसार विनियमित

किया जाएगा। लाहौर उच्च न्यायालय के नियमों में प्रासंगिक नियम यह निर्धारित किया गया है कि जो अधिवक्ता बैरिस्टर हैं, उन्हें बार में बुलाए जाने की तारीख के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी, जो अधिवक्ता बैरिस्टर नहीं हैं, वे तारीखों के अनुसार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के हकदार हो गए। यही सिद्धांत पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय पर लागू होता था, और लाहौर उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता को, जिसे नए उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के हकदार अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी गई थी, लाहौर उच्च न्यायालय में अपनी स्थिति के आधार पर अपनी वरिष्ठता की गणना करते थे। उन्होंने उस वरिष्ठता को नहीं खोया, जो बार काउंसिल अधिनियम, 1926 द्वारा संरक्षित थी, और हमें कोई कारण नहीं दिखता कि अनुच्छेद 233 के खंड (2) के प्रयोजन के लिए ऐसे अधिवक्ता के पास वही स्थिति नहीं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय में है, जहां वह प्रैक्टिस कर रहे हैं।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (3) के स्पष्टीकरण और अनुच्छेद 217 के खंड (2) के स्पष्टीकरण पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं के बारे में, और प्रस्तुत किया है कि जहां संविधान निर्माताओं ने इसे आवश्यक समझा। उन्होंने

विशेष रूप से एक उच्च न्यायालय में अवधि की गिनती के लिए प्रावधान किया जो पहले भारत में था। अनुच्छेद 124 और 217 अलग-अलग शब्दों में लिखे गए हैं और नागरिकता की एक अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख करते हैं जो अनुच्छेद 233 की आवश्यकता नहीं है, और हमें नहीं लगता कि अनुच्छेद 233 के खंड (2) की व्याख्या अनुच्छेद 124 और 217 में जोड़े गए स्पष्टीकरण के आलोक में की जा सकती है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एक स्व-निहित प्रावधान है।

ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में है, कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और खंड (1) के तहत राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से ही सेवा में नहीं है, खंड (2) में एक योग्यता निर्धारित की गई है और केवल यह आवश्यक है कि वह सात साल का एडवोकेट या प्लीडर होना चाहिए। खंड यह नहीं बताता है कि उस स्थिति को कैसे गिना जाना चाहिए और यदि पंजाब उच्च न्यायालय का एक अधिवक्ता बार में अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय में अपने प्रेक्टिस की अवधि को गिनने का हकदार है, तो हम अनुच्छेद 233 में कुछ भी नहीं देखते हैं, जो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करने की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए।

यदि अपीलकर्ता की ओर से प्रचारित व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है तो परिणाम क्या होगा? फिर, 15 अगस्त 1947 से शुरू होने वाले सात वर्षों तक, पंजाब उच्च न्यायालय के बार का कोई भी सदस्य जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा - एक परिणाम जिसे केवल तर्क की कमजोरी को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना है। हम अब तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की पहली दो प्रस्तुतियों पर आगे बढ़े हैं, और उसके आधार पर उनकी तीसरी प्रस्तुति पर विचार किया है। शायद यह जोड़ना आवश्यक है कि हमें यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने यह निर्णय लिया है कि अभिव्यक्ति 'रहा है' का अर्थ हमेशा वही होना चाहिए जो अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता कहते हैं। व्याकरण के कठोर नियम. इस पर गंभीरता से सवाल उठाया जा सकता है कि क्या एक जैविक संविधान की इतनी संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए, और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने हमारा ध्यान अनुच्छेद 5 (सी) जैसे संविधान के अन्य अनुच्छेदों की ओर आकर्षित किया है, जहां संदर्भ में अभिव्यक्ति का एक अलग अर्थ है। हमारा ध्यान मुबारक मजदूर बनाम के.के.बनर्जी (1) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की ओर भी आकर्षित किया गया है, जहां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (3) के परंतुक में होने वाली समान अभिव्यक्ति को एक अलग अर्थ दिया गया था। लोक अधिनियम, 1951 के, हम इस मामले को आगे बढ़ाने को अनावश्यक मानते हैं क्योंकि जिन उत्तरदाता पर अब हम

विचार कर रहे हैं वे पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने रहे जब उन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके पास सात साल से अधिक का कार्यकाल था। इसलिए नियुक्त किया गया. वे संविधान के अनुच्छेद 233 के खंड 2 के तहत नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से पात्र थे।

अब हम अन्य दो उत्तरदाता (हरबंस सिंह और पी.आर.सावनी) की ओर मुड़ते हैं, जिनके नाम तथ्यात्मक रूप से उस समय अधिवक्ताओं की सूची में नहीं थे, जब उन्हें जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी स्थिति क्या है? हम मानते हैं कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 233 की आवश्यकताओं को भी पूरा किया। हरबंस सिंह अपनी नियुक्ति के समय राज्य की सेवा में थे और उनकी ओर से पेश हुए श्री विश्वनाथ शास्त्री ने कहा है कि अनुच्छेद 233 का खंड (2) लागू नहीं होता है। हम मानते हैं कि भले ही हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि इन दोनों व्यक्तियों को बार से भर्ती किया गया था और उनकी नियुक्ति को खंड (2) की आवश्यकताओं के अनुसार परीक्षण किया जाना है, हमें यह मानना चाहिए कि उन्होंने उन आवश्यकताओं को पूरा किया है। वे लाहौर उच्च न्यायालय में नामांकित अधिवक्ता थे; यह विवादित नहीं है. उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947 के खंड 6 के तहत, उन्हें बार काउंसिल अधिनियम, 1926 लागू होने तक पंजाब उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के हकदार

अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी गई थी। उस अधिनियम की धारा 8 (2) (ए) के तहत उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार करे और बनाए रखे, जिसमें उनके नाम उस दिन दर्ज किए जाने चाहिए थे जिस दिन धारा 8 लागू हुई थी, अर्थात 28 सितंबर, 1948 को। धारा 8 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत उन्हें बार काउंसिल को देय 10 रुपये का शुल्क जमा करने की आवश्यकता थी। जाहिर है कि बार काउंसिल के गठन से पहले ऐसा भुगतान शायद ही किया जा सका हो। हम अपीलकर्ता और हस्तक्षेपकर्ताओं (बी.डी. पाठक और ओम दत्त शर्मा) के विद्वान अधिवक्ता से सहमत नहीं हैं कि परंतुक का प्रभाव उस अधिकार को छीनने का था जो इन उत्तरदाता को धारा 8(2) (ए) अधिनियम के तहत स्वचालित रूप से अधिवक्ताओं के रोल पर आना था। हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947 के खंड 6 और बार काउंसिल अधिनियम, 1926 की धारा 8(2)(ए) का संयुक्त प्रभाव यह था: 15 अगस्त, 1947 से 28 सितंबर तक, 1948 में, उन्हें पंजाब उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के हकदार अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी गई और 28 सितंबर, 1948 के बाद, वे स्वचालित रूप से पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के रोल में आ गए, लेकिन उन्हें बार काउंसिल को 10 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। 15 अगस्त, 1947 के बाद वे किसी भी समय या चरण में अधिवक्ता नहीं रहे और जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने तक वे पंजाब उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने रहे। संविधान के

अनुच्छेद 233 के खंड (2) के तहत पात्र होने के लिए उनके पास सात साल की आवश्यक स्थिति भी थी।

ये निष्कर्ष वास्तव में अपील का निपटारा करते हैं। हालाँकि, हम बता सकते हैं कि इन उत्तरदाता की ओर से कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 की धारा 4 पर आधारित एक वैकल्पिक तर्क भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। तर्क यह था कि लाहौर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकित उत्तरदाता भारत में किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रैक्टिस करने के हकदार थे, और भारत के संविधान के तहत लाहौर उच्च न्यायालय के नहीं रहने के बाद भी यह अधिकार छीना नहीं गया था। चूंकि हम उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, 1947 और बार काउंसिल अधिनियम, 1926 की धारा 8 से निकाले गए निष्कर्षों पर अपना निर्णय ले रहे हैं, हम कानूनी व्यवसायी अधिनियम 1879 की धारा 4 के आधार पर वैकल्पिक तर्क की जांच करना अनावश्यक मानते हैं।

अपीलकर्ता ने अपनी रिट याचिका का एक बड़ा हिस्सा इस तर्क का समर्थन करने के लिए समर्पित किया था कि उत्तरदाता की नियुक्ति खराब थी, क्योंकि इसने कुछ वैधानिक सेवा नियमों का उल्लंघन किया था। अपीलकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि पंजाब में वरिष्ठ नियुक्तियों की न्यायिक शाखा में आठ सूचीबद्ध पदों सहित 27 पद शामिल थे, इन आठ सूचीबद्ध पदों में से दो बार के सदस्यों के लिए और छह अधीनस्थ

न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए आरक्षित थे। प्रांत के विभाजन पर, यह कहा गया था, पूर्वी पंजाब को ग्यारह वरिष्ठ न्यायिक पद आवंटित किए गए थे, और बाद में संख्या बढ़ाकर बारह कर दी गई थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि इन बारह पदों में से एक तिहाई बार के सदस्यों के लिए आरक्षित था, एक तिहाई जिसे प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) कहा जाता था और बाकी योग्यता के आधार पर उपरोक्त दो स्रोतों में से किसी एक से भर्ती के लिए आरक्षित था। अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि जिस सेवा से अपीलकर्ता संबंधित है, उसके सदस्यों को नुकसान पहुंचाते हुए बार से बहुत से व्यक्तियों की भर्ती की गई है।

हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से पूछा कि वह हमें किसी विशेष वैधानिक नियम के बारे में बताएं जिसका उत्तरदाता 1 द्वारा नियुक्तियां करते समय उल्लंघन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ऐसे किसी भी वैधानिक नियम को इंगित करने में असमर्थ थे और एक सामान्य शिकायत करने के अलावा कि बार से बहुत से व्यक्तियों की भर्ती की गई है, वह यह भी प्रमाणित करने में असमर्थ थे कि सेवा सदस्यों के पक्ष में किए गए एक तिहाई आरक्षण का उल्लंघन किया गया है। किसी भी मामले में, जब तक कि यहां विचाराधीन किसी भी नियुक्ति को करने में वैधानिक नियम के उल्लंघन का स्पष्ट सबूत न हो, यह मुद्दा किसी भी चर्चा के लायक नहीं है। इस मामले में ऐसे सबूतों की बेहद कमी है।

परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और हर्जे के साथ खारिज कर दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक **न्यायिक अधिकारी** अखिलेश कल्याण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।